Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
December 2024
ISSN 2229-3388

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के युग में भारतीय अध्यापक शिक्षा का पुनरुत्थान: उदीयमान प्रवृत्तियां, चुनौतियां एवं परिवर्तन

डॉ. संदीप पाटील
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
पिन्टू कुमार
शोधार्थी, शिक्षा विभाग,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय शिक्षा जगत में एक निर्णायक परिवर्तन की अभिलाषा करती है, जो शिक्षक एवं अध्यापक शिक्षा को समूची शिक्षा व्यवस्था में सुधार के केंद्र में रखती है। प्रस्तुत शोध आलेख अध्यापक शिक्षा प्रणाली के समग्र बदलाव के लिए नीति के दूरदर्शी एवं समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। इसके तहत, पारंपरिक एवं विविक्त शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान से हटकर एकात्मिक, बहु-अनुशासनात्मक उपागम, लचीलेपन तथा डिजिटल साक्षरता पर आधारित एक अभिनव अध्यापक शिक्षा प्रतिमान की ओर बढ़ने वाले नवोन्मेष का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन विशेष रूप से, चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP), शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST), निरंतर व्यावसायिक प्रोन्नयन (CPD) की अनिवार्यता तथा क्षमता-आधारित अधिगम (Competency-based Learning) जैसे प्रमुख नीतिगत बदलावों की पड़ताल करता है।

नीतिगत दस्तावेजों, शैक्षणिक साहित्य एवं केस स्टडीज़ के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 अध्यापक व्यवसाय पेशे की "गरिमा एवं स्वायत्तता" को बहाल करने का रोडमैप प्रस्तुत करती है; वहीं दूसरी ओर इसके वास्तविक क्रियान्वयन में कई गहन संरचनात्मक, नियामक (Regulatory), तथा बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियाँ हैं। इनमें डिजिटल विभाजन (Digital Divide), बदलाव के प्रति पारंपरिक विरोध, समान पहुंच की कमी एवं रटकर सीखने की संस्कृति से बाहर निकलना शामिल हैं। प्रस्तुत शोध आलेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन बाधाओं को दूर करने तथा 21वीं सदी की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप संदर्भ-अनुकूल सुधारों के लिए सभी संबंधित हितधारकों (Stakeholders) के बीच एक संगठित, सहयोगी एवं पर्याप्त

संसाधनों वाले राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है, ताकि शिक्षकों को एक नए, जीवंत तथा समान भारतीय ज्ञान समाज के मुख्य निर्माता के रूप में सशक्त बनाया जा सके।

***मुख्य शब्द*: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, अध्यापक शिक्षा, बहु-अनुशासनात्मक उपागम (Multi-disciplinary approach), एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP)।**

प्रस्तावना :

किसी भी राष्ट्र के शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, दूरदर्शिता एवं उसकी प्रासंगिकता उसके शिक्षकों की क्षमता, समर्पण तथा उनकी तैयारी पर निर्भर करती है। इसी मूलभूत सत्य को आत्मसात करते हुए, चार दशकों के उपरांत भारत के पहले व्यापक शिक्षा सुधार के रूप में स्वीकार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने विद्यालयीन शिक्षा की नींव को मजबूत करने के लिए अध्यापक शिक्षा में मौलिक सुधार एवं पुनरोद्धार को एक अनिवार्य शर्त माना है। इस शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि "शिक्षक एवं अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता निश्चित करने वाले सबसे अहम कारक होंगे।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी समग्र (Holistic), लचीली, बहु-अनुशासनात्मक (Multi-disciplinary) तथा भविष्य-उन्मुख (Futuristic) शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है, जो वर्तमान के संकीर्ण एवं अलग-थलग शिक्षक प्रशिक्षण संरचनाओ को पूरी तरह बदलने की मांग करती है। इस नीतिगत दृष्टी को प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित करने के लिए शिक्षकों की भर्ती, प्रभावी प्रशिक्षण, सर्टिफ़िकेशन तथा उनके निरंतर व्यावसायिक प्रोन्नयन (CPD) के पद्धति पर मौलिक एवं नए सिरे से सोचने की तत्काल आवश्यकता है।

प्रस्तुत शोध लेख इसी नई तथा परिवर्तनकारी बदलावकारी सोच की पड़ताल करता है। इसके अंतर्गत, अध्यापक शिक्षा को नया रूप देने वाले समकालीन तथा उदयोन्मुख नवोन्मेष, इसे क्रियान्वित करने के मार्ग में आड़े आने वाली परम्परागत एवं नई संरचनात्मक चुनौतियों, तथा नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संस्थागत, शिक्षण-पद्धति (Pedagogical) तथा दार्शनिक स्तर पर बदलावों की प्रकृति का गहन विश्लेषण किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा की उदीयमान प्रवृत्तियां :

ANUSANDHANVALLARI
ISSN: 2229-3388

Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
December 2024
ISSN 2229-3388

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य गुणवत्ता एवं उत्तदायित्व पर ध्यान देते हुए अध्यापक शिक्षा में सुधार करना है (सिंह एवं कौर, 2023)। यह शिक्षा नीति 2020 एक व्यापक बदलाव की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसमें बिखरे हुए, सैद्धांतिक अंग पर अधिक बल देने वाले नियामक प्रतिमानों से हटकर अध्यापक शिक्षा के एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र ओर बढ़ने की बात कही गई है जो एकीकृत हो, अभ्यास-केंद्रित हो तथा सशक्तिकरण पर बल देता हो।

- **चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) :**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने एक नया ढांचा पेश किया है, जिसमें 2030 तक चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) को अपनाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को वर्तमान शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करना है (सिंह एवं कौर, 2023)। इस शिक्षा नीति के तहत 2030 तक, यह ज़रूरी है कि विद्यालयीन शिक्षक बनने के लिए सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों (ITEP) में रूपांतरित किए जाएं, जिससे अलग से चलने वाले बी. एड. महाविद्यालय धीरे-धीरे बंद हो जाएंगे। बहु-अनुशासनात्मक उच्च शिक्षा में चलाए जाने वाले इस एकीकृत प्रतिमान में, माध्यमिक या अलग से दी जाने वाले अध्यापक प्रशिक्षण की जगह, प्रारंभ से ही विषय की गहरी जानकारी तथा शिक्षण कौशलों (Pedagogical skills) को एक साथ सिखाया जाता है। इस बदलाव का उद्द्देश्य भविष्य के शिक्षकों को एक जीवंत बौद्धिक वातावरण में ढालना है, ताकि वे विभिन्न विषयों से परिचित हों तथा उनकी सोच का दायरा बढ़े (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

- **सख्त प्रवेश एवं निकास प्रणाली :**

केवल प्रेरित एवं योग्य उम्मीदवार ही अध्यापक व्यवसाय में आएं यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) के लिए प्रवेश एवं निकास की एक सख्त प्रणाली प्रारंभ की है। इस कार्यक्रम में प्रवेश एक सख्त, योग्यता-आधारित मानक जाँच प्रक्रिया से होगी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कराए जाने वाले उच्च गुणवत्ता की सामान्य प्रवेश परीक्षा एवं शिक्षण अभिक्षमता के लिए विशेष परिक्षण शामिल होंगे। निकास के विषय में, केवल 4 वर्ष का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने से ही

टीचिंग करियर की गारंटी नहीं मिलेगी। भर्ती के लिए योग्य होने के लिए, ग्रेजुएट को एक बेहतर एवं अधिक व्यापक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) उत्तीर्ण करना होगा। इस परिक्षण को विषय की समझ, शिक्षण कौशल तथा प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण क्षमता को सही ढंग से परखने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है।

- **बहु-अनुशासनात्मक एवं समग्र पाठ्यचर्या :**

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पाठ्यचर्या का पुनर्निर्माण किया जाएगा ताकि उसमें मूलभूत साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान, रचनात्मक आकलन, क्षमता-आधारित अधिगम तथा समावेशी अधिगम-पद्धति का समावेश किया जा सके। इसमें सामाजिक-भावनात्मक अधिगम, लैंगिक संवेदनशीलता, भारतीय परंपराओं का ज्ञान तथा अनुभव-आधारित अधिगम जैसी आधुनिक शिक्षा रीतियों पर विशेष बल दिया गया है।

- **प्रौद्योगिकी एकीकरण :**

यह शिक्षा नीति अध्यापक शिक्षा प्रदान करने (ऑनलाइन/ब्लेंडेड कोर्स) तथा भविष्य के शिक्षकों के लिए शिक्षण-अधिगम के साधन के तौर पर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर ज़ोर देती है। डिजिटल साक्षरता, शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा ऑनलाइन आकलन इसके प्रमुख अंग हैं। शिक्षण के तरीकों में प्रौद्योगिकी को अंतर्निहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर अधिगम अनुभव प्राप्त हो सकें (महानंदा, 2024)। व्यापक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए DIKSHA एवं SWAYAM जैसे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जा रहा है (वर्ल्ड बैंक, 2021)। NEP 2020 के तहत, "प्रौद्योगिकी एकीकरण" कक्षा में उपयोग में लाए जाने वाले एक वैकल्पिक उपकरण से बदलकर अध्यापक शिक्षा का एक मुख्य आधार बन गया है। इसने शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनके शिक्षण उपागम को पूरी तरह से बदल दिया है। सेवापूर्व एवं सेवारत कार्यक्रम अब डिजिटल शिक्षण विधियों (Digital pedagogy) को विकसित करने पर अधिक ज़ोर देते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वर्चुअल रियलिटी (VR) सिमुलेशन तथा इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स को आसानी से अपने पाठ में अन्तर्निहित कर सकें। अध्यापक शिक्षा में DIKSHA एवं SWAYAM जैसे राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, व्यापक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, यह शिक्षकों को अनुकूलित तथा कई भाषाओं के डिजिटल सामग्री के निर्माण करने के लिए भी तैयार कर रही है। इसके अलावा,

Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
December 2024
ISSN 2229-3388

शिक्षकों को डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति को ट्रैक करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप अधिगम में सहायता प्राप्त हो सकें। डिजिटल विभाजन को समाप्त करके तथा प्रारंभिक पाठ्यचर्या में प्रौद्योगिकी का समावेश करके, NEP 2020 यह सुनिश्चित करती है कि भविष्य के शिक्षक हाइब्रिड एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा के वातावरण में कार्यरत रहने एवं उसे आगे ले जाने के लिए पूरी तरह सक्षम हों।

- **सतत व्यावसायिक विकास :**

सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों की नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं उपदेशन (ट्रेनिंग एवं मेंटरशिप) पर ज़ोर दिया जा रहा है (राय, 2024)। केवल एक प्रशिक्षण से आगे बढ़ते हुए, यह शिक्षा नीति निरंतर व्यावसायिक प्रोन्नयन (CPD) के दृढ़ संस्कृति को बढ़ावा देती है, जिसमें व्यावसायिक विकास से जुड़े करियर में उन्नयन को अनिवार्य बनाया गया है। नेशनल मिशन फ़ॉर मेंटरिंग (NMM) तथा नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर (NDEAR) जैसे प्लेटफ़ॉर्म लगातार अधिगम समुदायों को बढ़ावा देंगे।

- **अभ्यास उन्मुखीकरण :**

मेंटरशिप, विद्यालय प्रशिक्षुता तथा निवासी प्रतिमान के माध्यम से विद्यालयों के साथ नियमित रूप से जुड़कर व्यावहारिक अभ्यास के समय में वृद्धि करने का उद्देश्य सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अंगों के बीच का अंतर कम करना है।

- **नवोन्मेषी एवं समावेशी शिक्षणशास्त्र :**

इस नीति में मातृभाषा में शिक्षा तथा लैंगिक संवेदनशील प्रशिक्षण पर बल दिया गया है, जो भारत की भाषाई विविधता के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, केरल की विद्याकिरणम पहल शिक्षकों को बहुभाषी कक्षा के लिए प्रशिक्षित करती है। इस नीति द्वारा पारंपरिक एवं रटने पर आधारित अधिगम रीतियों से हटकर, अब आधुनिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम "यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग" (UDL), अनुभव-आधारित गतिविधियों तथा प्रौद्योगिकी युक्त समावेशन पर अधिक जोर दिया गया है। भविष्य के शिक्षकों को विविध प्रकार की कक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है; इसमें विशेष संवेदनशीलता मॉड्यूल तथा सहायक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक-

Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
December 2024
ISSN 2229-3388

आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों (SEDGs) एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों (CWSN) की आवश्यकताओं को पूरा करना अंतर्निहित है। अलग-अलग विषयों को जोड़ने वाले उपागमों (cross-disciplinary approaches), बहुभाषी शिक्षण तथा राज्य व्यावसायिक प्रोन्नयन को शामिल करके, इस शिक्ष नीति का लक्ष्य शिक्षकों को केवल जानकारी देने वाले के तौर पर नहीं, अपितु ऐसे संवेदनशील सुलभकों (facilitators) के रूप में तैयार करना है जिससे समान, रचनात्मक एवं प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप अधिगम वातावरण का निर्माण हो सकें, ताकि कोई भी विद्यार्थी पीछे न छूटे।

- **विभिन्न करियर मार्ग :**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत, शिक्षण-अधिगम का परम्परागत एवं सामान्य उपागम अब कई तरह के अनेकों करियर रास्तों वाले एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र में बदल रहा है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षकों को ऐसे वातावरण के लिए विकसित कर रहे हैं जहाँ एक शिक्षक संरचनात्मक रूप से विशेष क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) का समावेश करने से शैक्षिक नेतृत्व, संस्थागत प्रशासन तथा नीति निर्माण जैसी भूमिकाओं में क्षमता आधारित एवं पारदर्शी रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है (NCTE, 2021)।

- **परिवर्धित प्रशिक्षण उपागम :**

इस शिक्षा नीति के तहत, अध्यापक शिक्षा में एक व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन दिखाता है, जिसमें पृथक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से एक समग्र एवं दृढ़ विकास की ओर बढ़ा जा रहा है। इस बदलाव का प्रमुख आधार अध्यापक शिक्षा को बहु-अनुशासनात्मक विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना तथा चर वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) का प्रारंभ करना है। यह कदम विषय के गहन ज्ञान को आधुनिक शिक्षणशास्त्र के विधियों का प्रशिक्षण, दृढ़ अभ्यास तथा आवश्यक विद्यालय प्रशिक्षुता के साथ मज़बूती से जोड़ता है।

- **कौशल एवं क्षमता विकास पर जोर :**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटकर सीखने के बजाय योग्यता आधारित मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) अब सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय कौशल विकास को प्राथमिकता

देती है (NCTE, 2022)। इस नीति के तहत अध्यापक शिक्षा को केवल सैद्धांतिक एवं रटने वाले प्रशिक्षण से हटाकर, मापनयोग्य एवं व्यावहारिक शिक्षण क्षमताओं की ओर मोड़ा है। आधुनिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम विशेष रूप से शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) के अनुरूप डिज़ाइन किए गए हैं (NCTE, 2021)। ये मानक शिक्षकों का मूल्यांकन केवल अकादमिक पदवी के आधार पर नहीं, अपितु कक्षा के प्रमुख कौशलों के आधार पर करते हैं। सेवा में आने से पूर्व ही शिक्षकों को आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, डिजिटल धाराप्रवाह तथा भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे उच्चस्तरीय संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपने विद्यार्थियों में भी ये कौशल विकसित कर सकें।

- **आजीवन अधिगम :**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, शिक्षण को केवल एक स्थिर करियर के बजाय लगातार विकास की यात्रा के रूप में देखा जाने लगा है। यह शिक्षा नीति मानती है कि तेज़ी से बदलते विश्व के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए, शिक्षकों को भी स्वयं को निरंतर बेहतर बनाते रहना होगा। इस सोच को बढ़ावा देने के लिए सभी शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए प्रति वर्ष 50 तसिकाओं का निरंतर व्यावसायिक प्रोन्नयन (CPD) प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। लचीले एवं मॉड्यूलर प्रशिक्षण के तरीकों (जिनमें DIKSHA भी शामिल है) के माध्यम से शिक्षक अपनी रूचि एवं कक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार अपने अधिगम को को दिशा दे सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में इतने गहन एवं दूरगामी परिणाम करने वाले संभावित परिवर्तन अध्यापक शिक्षा में निश्चित ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इस परिवर्तन को धरातल पर लाने के लिए अनेकों चुनौतियों को पार पाना आवश्यक है।

भारतीय अध्यापक शिक्षा की चुनौतियां :

इन दूरदर्शी नवोन्मेषों को ज़मीनी स्तर पर लाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; अगर रणनीतिक रूप से इनसे नहीं निपटा गया, तो ये बदलाव कमज़ोर पड़ सकता है या पटरी से उतर सकता है। किंग्स्टन एवं देवकी (2024) ने NEP 2020 के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है कि अध्यापक शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए बड़ी संरचनात्मक, वित्तीय एवं डिजिटल चुनौतियों से निपटना होगा, साथ ही बहु-अनुशासनात्मक,

प्रौद्योगिकी आधारित एवं उच्च-गुणवत्ता के प्रशिक्षण के अवसरों का भी लाभ उठाना होगा। हालांकि, इस व्यवस्था को बुनियादी सुविधाओं की कमी, पुराने पाठ्यक्रम तथा योग्य शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है, जो शिक्षकों की प्रभावी तैयारी में बाधा डालती हैं (राय, 2024) (महानंदा, 2024) (शाह, 2019)।

- **प्रौद्योगिकी एकीकरण :**

प्रौद्योगिकी एकीकरण स्वयं में अध्यापक शिक्षा के लिए एक जुड़ी चुनौती है। इस चुनौती की जड़ में डिजिटल एवं शिक्षणशास्त्र से जुड़ा एक गहरा अंतर है। जहां DIKSHA जैसे प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे डिजिटल स्त्रोत प्रदान करते हैं, वहीं अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों में वह प्रगत डिजिटल जानकारी नहीं है जो केवल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से आगे बढ़कर उससे प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी इसे एक जैसा क्रियान्वित करने में बाधा डालती है।

- **आर्थिक एवं संसाधन विषयक बाधाएं :**

कई राज्यों के पास चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता की कमी है, जिससे एकसमान प्रगति नहीं हो पा रही है (वर्ल्ड बैंक, 2022)। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप बताया गया है, लेकिन आर्थिक सहायता एवं संसाधनों की भारी कमी इसे प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित करने में एक बड़ी बाधा है। प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आधारभूत संरचना एवं नियामक चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है (मुखर्जी, 2024)। NEP 2020 के तहत अलग से चल रहे अध्यापक शिक्षा संस्थानों (TEIs) को पूरी तरह बंद करके उन्हें बेहतर सुविधाओं वाले, बहु-अनुशासनात्मक महाविद्यालयों में बदलने के लिए बुनियादी भौतिक सुविधाएँ, आधुनिक पुस्तकालय, प्रगत डिजिटल प्रयोगशालाएँ जैसी चीज़ों पर भारी निवेश की ज़रूरत है; फ़िलहाल ऐसी सुविधाएं वर्तमान में अधिकतम ज़्यादातर ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी संस्थानों में नहीं हैं। ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिजिटल उपकरणों की कमी है, जिससे शैक्षिक प्रौद्योगिकी (EdTech) को अपनाने में बाधा आती है (ASER, 2022)। ग्रामीण इलाकों के केवल 23% शिक्षकों के पास कंप्यूटर की सुविधा है (नीति आयोग, 2021)।

- **शिक्षकों की कमी :**

इस शिक्षा नीति के महत्वाकांक्षी परिवर्तन के लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए बड़ी संख्या में विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। भविष्य के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में काफी कमी है (राय, 2024)। भारत में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में एवं विज्ञान, गणित, स्थानीय भाषाओं तथा विशेष शिक्षा जैसे खास क्षेत्रों में शिक्षकों की लगातार कमी बनी हुई है। यह कमी तब अधिक बढ़ जाती है जब अगली पीढ़ी के व्यावसायिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में सक्षम, उत्तम क्षमता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षकों की भी भारी कमी है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी समस्याएं, योग्य शिक्षकों की कमी तथा वित्तीय सहायता की कमी के कारण शिक्षकों की कमी तथा निरंतर व्यावसायिक प्रोन्नयन की सीमाएं और भी बढ़ जाती हैं (कपाड़िया, 2023) (किंग्स्टन एवं देवकी, 2024)। इन बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरे बिना तथा सशक्त भर्ती प्रक्रिया बनाए बिना, वर्तमान कार्यबल पर काम का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा, जिससे NEP 2020 में परिकल्पित वैयक्तीकृत, क्षमता आधारित एवं समावेशी अधिगम वातावरण को क्रियान्वित करने की व्यवस्था की क्षमता बुरी तरह सीमित हो जाएगी।

- **आधुनिक शिक्षणशास्त्र के लिए पाठ्यचर्या का पुनर्निर्माण :**

वर्तमान पाठ्यचर्या वैश्विक मानकों या आधुनिक कक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं (महानंदा, 2024)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय अध्यापक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए आधुनिक शिक्षणशास्त्र के लिए पाठ्यचर्या का पुनर्निर्माण एक बड़ी संरचनात्मक चुनौती है। दशकों से, अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या बिखरे हुए, अत्यंत कठोर एवं पुराने सिद्धांतों पर आधारित रहे हैं, जो आज की कक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इस पुराने ढांचे को पूरी तरह बदलने के लिए एक ऐसे प्रतिमान की आवश्यकता है जो लचीला हो तथा जो कई विषयों को एक साथ लाए जैसे कि नया अनिवार्य एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP), जिसमें मुख्य विषयों को आधुनिक शिक्षण-पद्धतियों के साथ प्रभावी रूप से जोड़ने की आवश्यकता है। मुख्य चुनौती केवल पाठ्यपुस्तकों के पुनर्लेखन की नहीं है, अपितु ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करने की है जिसमें प्रौद्योगिकी द्वारा अधिगम, सामाजिक-भावनात्मक बोध तथा क्षमता आधारित मूल्यांकन की पद्धतियों को व्यावहारिक रूप से शामिल किया जा सके।

- **नीतिगत बदलावों का अनुकूलन :**

NEP 2020 के तहत भारतीय अध्यापक शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने में नीतिगत सुधारों को अपनाना एक जटिल प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक चुनौती है। इस नीति के लिए व्यापक स्तर पर संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है। विशेष रूप से, सभी विभक्त प्रशिक्षण संस्थानों को बहु-अनुशासनात्मक विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना यह एक बड़ी चुनौती है। भ्रष्ट एवं सुस्त नौकरशाही, विभिन्न नियामक अधिकार-क्षेत्रों का टकराव तथा संस्थानों का विरोध इन कारणों से यह बदलाव होने में कठिनाई है। साथ ही, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं प्रशासकों को परम्परागत एवं कठोर प्रथाओं को त्याग कर लचीले, विकल्प आधारित आधारित श्रेयांक प्रणाली (CBCS) तथा शिक्षकों के किए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) जैसी आधुनिक नियामक प्रणाली को गंभीरतापूर्वक अपनाने की आवश्यकता है।

- **संरचनात्मक एवं संस्थानात्मक अवरोध :**

विभिन्न विभक्त बी. एड. महाविद्यालयों को बहु-अनुशासनात्मक विश्वविद्यालयों में मिलाना एक व्यापक संभारिकी एवं प्रशासनिक कार्य है। कई विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को स्वीकारने एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, सामग्री, विशेषज्ञता प्राप्त संकाय सदस्य, तथा प्रशासनिक लचीलेपन की कमी है। अभी हज़ारों विभक्त अध्यापक शिक्षा संस्थान (TEIs) हैं, जिनमें से कई के पास बहु-अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना नहीं है (चक्रवर्ती, 2022)। गुणवत्ताहीन अध्यापक शिक्षा संस्थानों को बंद करना आवश्यक है, अपितु यह काम संभार-तंत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत कठिन है। अध्यापक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता कई संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) तथा राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल पर निर्भर करती है। अधिकार-क्षेत्रों का टकराव तथा नौकरशाही का भ्रष्टाचार एवं सुस्ती इसमें बाधा बने हुए हैं।

- **परिवर्तन को प्रतिरोध :**

अध्यापक शिक्षा में परिवर्तन के लिए एक मुलभुत चुनौती परंपरागत रटकर सीखने तथा परीक्षा केंद्रित पठनपाठन की संस्कृति को त्यागकर क्षमता आधारित, विद्यार्थी केन्द्रित एवं आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले शिक्षण-

अधिगम की कार्यसंस्कृति को स्वीकारना अतिआवश्यक है। इस परिवर्तन हेतु शिक्षकों की सोच एवं कार्यप्रणाली के साथ साथ अभिभावकों एवं समाज की सोच एवं अपेक्षाओं में भी बदलाव की आवश्यकता है। केवल परीक्षा के लिए पढ़ाने से क्षमता के लिए पढ़ाने की ओर बढ़ने हेतु शिक्षकों की सोच में आमूलाग्र परिवर्तन की आवश्यकता है। कई अनुभवी शिक्षक, जो परंपरागत व्याख्यान शैली के आदी हैं, उन्हें पृच्छा आधारित तथा विद्यार्थी केंद्रित अधिगम विधियों को अपनाने में कठिनाई होती है (भट्टाचार्य एवं कुमार, 2021)। साथ ही, अध्यापक प्रशिक्षण के परंपरागत संस्थानों को NEP 2020 के अनुरूप पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करने में संकोच का सामना करना पड़ रहा है। NCERT (2023) के एक सर्वेक्षण के अनुसार 45% शिक्षक क्षमता आधारित शिक्षण विधियों के लिए स्वयं को तैयार नहीं मानते थे।

- **डिजिटल विभाजन एवं संसाधन असमानताएँ :**

हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य अध्यापक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, लेकिन डिजिटल विभाजन एवं संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां इसे पूरी तरह से क्रियान्वित करने में बाधा बन सकती हैं। इस शिक्षा नीति के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इन बाधाओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है (लक्ष्मी, 2023)। प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिगम पर ज़ोर देने के लिए एक निश्चित स्तर की डिजिटल अभिगम्यता एवं साक्षरता की आवश्यकता होती है, जो भारत के विभिन्न भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्तरों पर एकसमान नहीं है। ग्रामीण तथा कम संसाधनों वाले संस्थान पीछे छूट सकते हैं। तथापि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी एकीकरण बढ़ावा देती है, लेकिन देश के ग्रामीण क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में अभी भी स्थिर इंटरनेट एवं हार्डवेयर की कमी है। इससे डिजिटल शिक्षण-पद्धति में अंतर निर्माण होता है, जहाँ शहरी केंद्रों के शिक्षक आगे बढ़ते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक मूलभूत अभिगम्यता के लिए भी संघर्ष करते हैं।

अपेक्षित परिवर्तन के लिए उठाएं जा रहे महत्वपूर्ण कदम :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन को साकार करने के लिए चुनौतियों को पार कर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

1. शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल (NISHTHA): यह देशव्यापी कार्यक्रम 40 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता एवं डिजिटल उपकरणों में प्रशिक्षित करता है।

2. बहुभाषी शिक्षा (MLE) पहल: तमिलनाडु एवं ओडिशा जैसे राज्य अध्यापक प्रशिक्षण में क्षेत्रीय भाषाओं को समाविष्ट कर रहे हैं।

3. माइक्रो-क्रेडेंशियलिंग: SWAYAM जैसे प्लेटफ़ॉर्म AI, समावेशी शिक्षा एवं STEM शिक्षण-पद्धति में मॉड्यूलर कोर्स उपलब्ध कराते हैं (NCTE, 2023)।

4. शैक्षणिक संस्थान: TISS एवं NCERT जैसे संस्थान NEP के अनुरूप प्रतिमान को समाविष्ट करने के लिए पाठ्यचर्या का पुनर्निर्माण कर रहे हैं।

5. NGO एवं CSR पहल: "प्रथम" तथा "अक्षय पात्र" जैसे संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी को पूरा कर रहे हैं (ASER, 2022)।

आवश्यक बदलाव :

अध्यापक शिक्षा में बदलाव के लिए कुछ कदम तत्काल प्रभाव से उठाना आवश्यक है, वे निम्नानुसार हैं।

1. चरणबद्ध एवं प्रासंगिक कार्यान्वयन :

जल्दबाजी में किया गया सबके लिए एकसमान क्रियान्वयन का तरीका विफल हो सकता है। राज्यों एवं संस्थानों को आरंभिक परीक्षणकरते हुए उसे आधार पर स्पष्ट एवं चरणबद्ध लक्ष्यों के साथ प्रासंगिक रोडमैप बनाने की स्वतंत्रता आवश्यक है।

2. अध्यापक शिक्षकों में निवेश :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहु-अनुशासनात्मक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एकीकरण तथा अनुसन्धान पर ज़ोर देती है। यह निरंतर व्यावसायिक प्रोन्नयन के माध्यम से आजीवन अध्ययन की सुविधा प्रदान करती है तथा लचीले, समग्र प्रतिमान के माध्यम से नवोन्मेष को बढ़ावा देती है। टाटा सामाजिक विज्ञानं संस्थान (TISS) का पार-अनुशासनात्मक ITEP जैसे सफल उदाहरण, हितधारकों के सहयोग से व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करने की क्षमता दिखाते हैं (कपाड़िया, 2023)। शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए एक

व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम में बहु-अनुशासनात्मक, अनुभव आधारित, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली तथा प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षणशास्त्र पर जोर दिया जाना चाहिए।

3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी :

रणनीतिक सार्वजनिक –निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के माध्यम से आधारभूत संरचना निर्माण, सुविधा विकास, संसाधनों की उपलब्धता, डिजिटल उपकरणों का निर्माण, डिजिटल टूल्स निर्माण तथा शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक प्रोन्नयन के लिए गुणवत्तापूर्ण बहुभाषी सामग्री आदी क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षा बहुत ही प्रभावी तरीके से लाभान्वित हो सकती है। अपितु, ऐसा करते समय समानता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसे सशक्त नियामक कार्यप्रणाली के तहत संचालित किया जाना चाहिए।

4. सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण :

बदलाव लाने के लिए सहयोगी नेटवर्क के निर्माण की आवश्यकता होती है, जैसे विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में सार्थक साझेदारी, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक अधिगम समुदायों (PLCs) का निर्माण, तथा सशक्त उपदेशन (Mentoring) प्रणाली, जहाँ अनुभवी शिक्षक नए शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रारंभ से ही ऐसी रणनीतियों को शामिल करना होगा जो विविध प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करें तथा समानता को बढ़ावा दें (सरदार और अन्य, 2024)।

5. अध्यापक शिक्षा में मूल्यांकन में सुधार :

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दूरदर्शिता के अनुरूप आकलन प्रक्रिया को ढालना आवश्यक है। रटने पर आधारित परीक्षाओं से हटकर पोर्टफोलियो, कक्षा प्रदर्शन आकलन एवं चिंतनशील पत्रिका का उपयोग करने से शिक्षणशास्त्र में वास्तविक बदलाव आ सकेगा।

6. विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण एक कठोर, सभी के लिए एकसमान प्रशिक्षण प्रतिमान से स्थानीयकृत व्यावसायिक विकास में स्थानांतरित करके भारतीय अध्यापक शिक्षा में बदलाव के लिए अत्यंत आवश्यक नींव के रूप में कम कर सकता है। ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी), क्लस्टर संसाधन केंद्र (सीआरसी),

तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) जैसे जमीनी स्तर के संस्थानों को सशक्त बनाकर, यह दृष्टिकोण सुनिश्चित कर सकता है कि निरंतर व्यावसायिक प्रोन्नयन सीधे क्षेत्र-विशिष्ट कक्षा चुनौतियों एवं सांस्कृतिक संदर्भों को संबोधित करता है। यह सूक्ष्म-स्तरीय सशक्तिकरण न केवल शिक्षकों की जमीनी स्तर की उत्तरदायित्व को बढ़ाता है, अपितु अभ्यास के स्थानीय समुदायों का भी निर्माण करता है जो दीर्घकालिक संस्थागत उत्कृष्टता को आगे बढ़ा सकते हैं।

7. वैश्विक बेंचमार्किंग :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षा में ग्लोबल बेंचमार्किंग, स्थानीय शिक्षण पद्धतियों को उच्चस्तरीय वैश्विक मानकों के साथ जोड़कर तथा साथ ही भारतीय शैक्षिक मूल्यों को बनाए रखकर भारतीय प्रणाली का पुनरुत्थान कर सकती है। अध्यापक शिक्षा में उच्चतम वैश्विक अभ्यास अपनाने से भारतीय शिक्षक न केवल आधुनिक, प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षा के लिए तैयार हों, अपितु वे ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करने में भी सक्षम हों जो वैश्विक स्तर पर समर्थ एवं दूरदर्शी हों।

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भारतीय अध्यापक शिक्षा का पुनर्गठन केवल उपाधि की अवधि या पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, अपितु यह देश के शैक्षिक परिदृश्य में मूलगामी परिवर्तन करने का एक ऐतिहासिक एवं साहसी कदम है। यह नीति शिक्षकों के सामाजिक एवं व्यावसायिक महत्ता को पुन:स्थापित करते हुए उन्हें भविष्य के लिए तैयार तथा संवेदनशील उपदेशक बनाने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है। डिजिटल साक्षरता, समावेशी शिक्षा, बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण तथा आजीवन अध्ययन जैसे उभरते हुए नवोन्मेष अध्यापक शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की आशा निर्माण करते हैं। इसके विपरीत, इस शिक्षा नीति की दूरदर्शिता एवं कक्षा की वास्तविकता के बीच का अंतर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आधारभूत संरचना की कमी, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, संस्थागत कमज़ोरियाँ, पारंपरिक उपागम में बदलाव का विरोध तथा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानदंड तथा निरंतर व्यावसायिक प्रोन्नयन जैसी व्यवस्थाओं को पूरे देश में समान रूप से लागू करना अभी भी एक गंभीर चुनौती है।

अतः इस परिवर्तन की यशस्विता केवल सैद्धांतिक सुधारों से नहीं, अपितु केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, पर्याप्त वित्तीय निवेश, तथा नीति के लगातार मूल्यांकन पर निर्भर करती है। इस परिवर्तन हेतु व्यापक कार्यसंस्कृति बदलाव की आवश्यकता है, जहाँ नीति निर्माताओं से लेकर शिक्षकों तक, सभी हितधारकों को एक साथ प्रयासरत होना होगा। यदि इस दूरदर्शी रणनीति को पूरी राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं सामुदायिक भागीदारी के साथ प्रामाणिकता से क्रियान्वित किया जाता है, तो यह सुधार भारतीय कक्षा एवं वैश्विक मानकों के बीच की खाई को पूरी तरह पाट देगा। इससे शिक्षकों की एक ऐसी सशक्त तथा प्रेरणादायी पीढ़ी तैयार होगी जो 21वीं सदी की ज्ञान संचालित विश्व में भारत के नागरिकों का उचित मार्गदर्शन कर देश को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति - विश्वगुरु के रूप में आगे ले जाने में सक्षम होगी।

संदर्भ :

[1] एएसईआर सेंटर. (2022). *एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (रूरल) 2022*. प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन.
a. https://asercentre.org/wp-content/uploads/2022/12/ASER-report_2022-1.pdf

[2] भट्टाचार्य, एस. एवं कुमार, पी. (2021). चैलेंजेज इन इम्प्लेमेंटिंग एनइपी 2020: ए टीचर्स पर्सपेक्टिव. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल पालिसी एंड प्रैक्टिस*, *15*(1), 34-46.

[3] चक्रवर्ती, आर. (2022). स्ट्रेटेजीज तो इम्प्लेमेंट इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) इन रेस्पेक्ट टू एनईपी 2020. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ नोवेल रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट*, *7*(4), 12–18.

[4] कपाडिया, एन. (2023). रेफोर्मिंग टीचर एजुकेशन: अपोर्चूनिटीज एंड चैलेंजेज अंडर एनइपी 2020. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स,* *11*(1), 159-162. https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2301625.pdf

[5] किंग्स्टन, आर. एंड देवकी, एन. (2024). *इम्प्लेमेंटेशन ऑफ़ एनइपी 2020:* चैलेंजेज एंड अपोर्चूनिटीज *इन टीचर एजुकेशन*. शंलाक्स पब्लिकेशन्स.

[6] लक्ष्मी, वी. (2023). रिवायटीलाइज़िंग टीचर एजुकेशन: अस्सेस्सिंग दी इम्प्लीकेशन्स ऑफ़ एनइपी 2020. *इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडीसीप्लिनरी रिसर्च,* *5*(6), 1-7. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i06.8470

[7] महानंदा, आइ. (2024). ओवरकमिंग दी चैलेंजेज ऑफ़ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया. *इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडीसीप्लिनरी रिसर्च*, *6*(2). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.17266

[8] मुखर्जी, एस. (2024). रि-इमाजीनिंग टीचर एजुकेशन इन इंडिया: अस्सेस्सिंग दी इम्प्लीकेशन्स ऑफ़ नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020. *इंटरनेशनल मल्टीडीसीप्लीनरी रिसर्च जर्नल,* *6*(1), 174-181. https://doi.org/10.54476/ioer-imrj/718522

[9] नीति आयोग. (2021). *इंडिया'ज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: चैलेंजेज एंड अप्पोर्तुनिटीज*. भारत सरकार. https://www.niti.gov.in/role-digital-infrastructure-socio-economic-development

[10] राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद. (2021). *नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. https://web.ncte.gov.in/

[11] राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद. (2022). *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. https://web.ncte.gov.in/en

[12] राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद. (2023). *इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी): करिकुलम फ्रेमवर्क [गाइडलाइन्स]*. भारत सरकार. https://ksbed.ac.in/wp-content/uploads/2023/08/NCTE-ITEP-Book-Curriculum-framework-2023-MRNB.pdf

[13] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद. (2023). *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. https://www.ncert.nic.in/pdf/NCFSE-2023-August_2023.pdf

[14] राय, आर. (2024). *टीचर एजुकेशन इन इंडिया एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स*. बी. पी. इंटरनेशनल. https://doi.org/10.9734/bpi/mono/978-81-974774-3-0

[15] सरदार, एस., सहा, एस., एवं अखंड, एम्. (2024). दी चैलेंजेज एंड अपोर्चुनिटीज ऑफ़ एनइपी-2020 इन दी रिफरेन्स ऑफ़ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया: एन ओवरव्यू. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडीसीप्लीनरीरिसर्च पर्सपेक्टिव, 2*. 45-56. https://doi.org/10.61877/ijmrp.v2i10.207

[16] शाह, आर. ए. (2019). टीचर एजुकेशन इन इंडिया, इश्यूज एंड चैलेंजेज. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन इन्फोर्मेटीव् साइंस एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज, 3*(2), 43-47. https://doi.org/10.46828/ijrisat.v3i2.61

[17] शिक्षा मंत्रालय (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_update/NEP_final_HI_0.pdf

[18] सिंह, एस. एवं कौर, आर. (2023). ट्रांस्फोर्मिंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ़ एनइपी-2020. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एप्लाइड रिसर्च, 9*(4), 47-50. https://www.allresearchjournal.com/archives/2023/vol9issue4/PartA/9-4-4-395.pdf

[19] वर्ल्ड बैंक. (2022). *इफेक्टिव टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी: टेक्नोलॉजी-बेस्ड स्ट्रेटेजीज फ्रॉम अक्रॉस दी ग्लोब टू एन्हांस टीचिंग प्रैक्टिसेज- ए गाइडेंस नोट*. वर्ल्ड बैंक. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099835106172233833/pdf/P1742520d4de390610b784047359e0cefc7.pdf